Publication	Amar Ujala	Language	Hindi
Edition	New Delhi	Journalist	Bureau
Date	19/01/2024	Page no	13
CCM	4.93		

Joined hands for cooperative venture

सहयोगात्मक उद्यम के लिए हाथ मिलाया

नई दिल्ली। दिल्ली खादी व दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लिमिटेड ने सहयोगात्मक उद्यम के लिए हाथ मिलाया। वह पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाएंगे। सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। ब्यूरो

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD

खाद्य सुरक्षा के लिए दाने-दाने का किया जाएगा भंडारण

अरविंद शर्मा • नई दिल्ली

देश की बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण क्षमता प्राप्त करने पर काम शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य अन्न भंडारण की जरूरतों को पूरा करना है। देश में अभी कुल उत्पादन के 47 प्रतिशत अनाज के भंडारण की ही क्षमता है। प्रबंध में कमी के चलते प्रतिवर्ष लगभग 14 से 16 प्रतिशत तक अनाज बर्बाद हो जाता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर कैबिनेट ने बीते वर्ष मई में सहकारी क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति भी बनाई गई थी।

अन्न भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए तीन पक्षों को शामिल किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) एवं पैक्सों के साथ मिलकर देश की मौजूदा अन्न भंडारण क्षमता को 1,450 लाख टन से बढ़ाकर 2,150 लाख टन करने का प्रयास शुरू किया है। राज्यों को गारंटी देनी है और पैक्सों को जमीन उपलब्ध करानी है जबकि निर्माण का काम एनबीसीसी करेगा।

पहले चरण में देशभर में 1,500 गोदामों के निर्माण का जिम्मा एनबीसीसी को सौंपा गया है। 50 के लिए करार हो चुका है। राज्यों की सहमति मिल चुकी है। निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 50 गोदामों के लिए फरवरी में करार होना है। भारत अनाज उत्पादन में आगे है लेकिन भंडारण क्षमता में बहुत पीछे। कृषि क्षेत्र में सुधारों के कारण देश में प्रत्येक वर्ष उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किंतु उस अनुपात में गोदाम नहीं हैं। अभी देश में अन्न भंडारण की क्षमता मात्र 1,450 लाख टन की है। अगले पांच वर्षों में लक्ष्य इसमें 700 लाख टन की वृद्धि करना है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 3,200 लाख टन विभिन्न खाद्यान्न का उत्पादन होता है। भंडारण क्षमता बढ़ाने का काम कई चरणों में पूरा होगा। अभी सभी राज्यों से प्रत्येक जिले में पांच-पांच पैक्सों का चयन करने के लिए कहा गया है। बाद में इसे ब्लाक स्तर पर करना है एवं अंत में केंद्र की योजना सभी पैक्सों में अनाज गोदाम बनाने की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में 15 पैक्सों में गोदाम निर्माण किया जा रहा है।

भंडारण के अभाव में बर्बाद होने वाला लाखों टन अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने के बाद बचाया जा सकेगा। साथ ही किसानों को सस्ते दाम पर फसल बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

- दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण क्षमता हासिल करने पर काम शुरू
- गोदाम के अभाव में हर साल 14 से 16 प्रतिशत अन्न की हो जाती है बर्बादी

1,450 लाख टन अभी है अन्न भंडारण क्षमता

47 प्रतिशत अनाज के भंडारण की ही क्षमता देश में अभी

2150 लाख टन करने का लक्ष्य

- देश में प्रत्येक वर्ष अन्न उत्पादन में हो रही है वृद्धि

घरेलू खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा भारत

जाब्यू, नई दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मिनिस्ट्रियल कान्फ्रेंस में भारत घरेलू खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। भारत किसी भी देश के दबाव में आकर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने वाला है। 164 सदस्य देशों वाले डब्ल्यूटीओ का 13वां मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस आगामी 26-29 फरवरी को अबूधाबी में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विकसित देश भारत द्वारा गेहूं व चावल जैसे अनाज के निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल खड़ा कर सकते हैं।

Internal (for authorised circulation only)

Downloaded from SAMVAD